राज एक्सप्रेस, भोपाल
20 AUG 2011

शिवराज ने पढ़ लिया जनता के मन को

शेहला मसूद हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश प्रदेश की जनता की इच्छा के अनुरूप है। सरकार ने समझ ली यह बात।

इसके लिए प्रदेश सरकार, खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने आरटीआई (सूचना का अधिकार) कार्यकर्ता शेहला मसूद हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश बिना समय गंवाए कर दी है। उधर, शेहला के परिजनों ने मांग की और इधर मुख्यमंत्री ने वह मांग स्वीकार कर ली। यह सही है कि शेहला मसूद हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने का मतलब यह नहीं है कि प्रदेश के सभी आरटीआई कार्यकर्ता सुरक्षित हो गए हैं। यह तो तभी संभव होगा, जब इसके लिए अलग से उपाय किए जाएंगे और उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही ऐसा कुछ करेगी भी कि प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। अलबत्ता, इस घटना की जांच सीबीआई से कराने का अर्थ यह तो है कि मुख्यमंत्री ने इस कांड को गंभीरता से लिया है। आरटीआई लागू होने से लेकर अब तक देशभर में 17 कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं, पर यह दूसरा मौका है, जब ऐसी किसी घटना की जांच सीबीआई करेगी। उल्लेखनीय है कि अमित जेठवा हत्याकांड की जांच गुजरात की मोदी सरकार ने भी सीबीआई को सौंपी है।

उधर, वैसे तो महाराष्ट्र आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में अव्वल है, पर पुणे के सतीश शेट्टी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग जोर-शोर से उठाई गई थी, तो भी महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। शेहला मसूद के रूप में मध्यप्रदेश ने अपना पहला आरटीआई कार्यकर्ता खोया है। यह सही है कि हम अपनी पुलिस पर जहां अविश्वास नहीं कर सकते हैं, तो वहीं सीबीआई बहुत अधिक भरोसेमंद नहीं है, तो भी उम्मीद की जानी चाहिए कि सीबीआई हत्याकांड की तह तक पहुंचेगी। प्रदेश की जनता यही चाहती है कि हत्यारे दंडित हों और मुख्यमंत्री ने जनता के मन की बात समझ ली है।